

प्रेषक,

डा० रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग-02

देहरादून: दिनांक 17, जनवरी, 2015:

विषय— वित्तीय वर्ष 2014-15 में डेरी विकास योजना (सामान्य) के अन्तर्गत निदेशालय डेरी विकास के कार्यालय एवं आवासीय परिसर की स्थापना हेतु प्रथम चरण के कार्यों की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-581-83/लेखा-निदेशालय भवन नि० पत्रा०/2014-15, दिनांक 09 सितम्बर, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डेरी विकास योजना (सामान्य) के अन्तर्गत उक्त विषयक कार्य हेतु गठित आगणन ₹ 24.62 लाख के सापेक्ष टी०ए०सी० द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि ₹ 17.24 लाख की प्रशासनिक/वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 17.24 लाख निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
2. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
3. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मददे नजर विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
4. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली-भाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।
5. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219 (2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
6. यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जाय।
7. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 (समय-समय पर यथा संशोधित) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाए।
9. द्वितीय चरण के विस्तृत आगणन को प्रेषित करते समय यह प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाये कि "प्रथमचरण के प्रस्तावित कार्य पूर्ण हो चुके हैं"।

2- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2404-डेरी विकास-00-आयोजनागत-102-डेरी विकास परियोजनायें-03-डेरी विकास की योजना-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-122(P)/XXVII-4/2013, दिनांक 03 जनवरी, 2015 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा० रणबीर सिंह)

प्रमुख सचिव।

संख्या- 23 —(1)/XV-2/2015तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ अफसर-प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मा० मंत्री, दुग्ध को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)

उप सचिव।